भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
आर्थिक कार्य विभाग

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2000**

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

**डिजिटल रुपया**

**2000. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार द्वारा प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किए गए डिजिटल रुपये का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने पर विचार कर रही है;
(ग) क्या सरकार मानती है कि डिजिटल रुपये के शुरू होने के पश्चात् अगले तीन वर्षों में नकद लेनदेन कम हो जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) डिजिटल रुपये को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए /उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में सीबीडीसी में प्रायोगिक परियोजनाएं लॉन्च की हैं। थोक खंड (ई₹-डब्ल्यू) में डिजिटल रुपये में पहली प्रायोगिक परियोजना 1 नवंबर, 2022 को लॉन्च की गई थी, जिसे सरकारी प्रतिभूतियों के निपटान में द्वितीयक बाजार के लेनदेन में उपयोग किया था। इसके अलावा, खुदरा डिजिटल रुपये (ई₹-आर) की पहली प्रायोगिक परियोजना 1 दिसंबर, 2022 को लॉन्च की थी। प्रायोगिक परियोजना सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) में चुनिंदा स्थानों को कवर कर रही है, जिसमें भाग लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल हैं।

ई₹-आर एक डिजिटल टोकन के रूप में है जो विधिक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन्हीं मूल्यवर्गों में जारी किया जा रहा है जहां वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यह वित्तीय मध्यस्थों, यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रदत्त और मोबाइल फोन / उपकरणों पर संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई₹-आर के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे। ई₹-आर भौतिक नकदी जैसे विश्वास, सुरक्षा और निपटान की सुविधाएँ प्रदान करता है। नकदी के मामले में, यह कोई ब्याज नहीं कमाएगा और इसे मुद्रा के अन्य रूपों जैसे कि बैंकों में जमा में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) से (घ): सीमा-पार भुगतान में दक्षता लाना सीबीडीसी को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। तदनुसार, थोक और खुदरा खंड दोनों में सीमा-पार भुगतान सहित सीबीडीसी के उपयोग के मामलों के आगे की प्रायोगिक परियोजनाओं को प्रायोगिक परियोजनाओं के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के माध्यम से किया जाना है। इसके अतिरिक्त, मीडिया अभियानों के माध्यम से डिजिटल रुपये की विभिन्न विशेषताओं को पहले से ही जनता के बीच प्रसारित किया जा रहा है।
अर्थव्यवस्था में नकदी/बैंक नोटों की मात्रा जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, गंदे बैंक नोटों के प्रतिस्थापन और भुगतान के गैर-नकदी तरीकों में वृद्धि के कारण बैंक नोटों की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

*****